



न्यूज़ ब्रीफ

एफपीआई ने अगस्त में अब तक शेयर बाजार में डाले 23,544 करोड़, इस वर्ष अब तक विदेशी निवेशक शेयरों में 2,30,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली कर चुके



नई दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजार में अपनी लिवाली तेज कर दी है, इस महीने अब तक 23,544 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया है। जुलाई में किए गए 20,200 करोड़ रुपये के निवेश के बाद यह लगातार दूसरे महीने की लिवाली है, जो चार महीनों की भारी बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों, रुपये की स्थिरता और बाजार की मजबूत संभावनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने जून से मार्च तक लगातार चार महीनों में भारी पूंजी निकाली थी। हालांकि, हाल की इस खरीदारी के बावजूद, इस वर्ष अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में 2,30,000 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध बिकवाली कर चुके हैं, जो पिछले वर्ष की कुल निकासी से भी अधिक है। बाजार के जानकारों ने बताया कि पहली तिमाही के बेहतर कार्पोरेट नतीजे, रुपये की स्थिरता और व्यापक बाजार की मजबूत वृद्धि संभावनाएं एफपीआई की वापसी के मुख्य कारण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी निवेशक बड़े बैंकिंग और आईटी शेयरों के बजाय, अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्यांकन के बावजूद चुनिंदा मझौली कंपनियों के शेयरों में पैसा लगा रहे हैं।

महिंद्रा लाइफस्टाइलर पिकअप से वैश्विक बाजार में बढ़ाएगी मौजूदगी, कंपनी कई देशों में उतारेगी नया माडल, भारत में 2027 में होगा लान्च



नई दिल्ली। घरेलू वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) अपने नए पिकअप वाहन स्कांर्पियो लाइफस्टाइलर के साथ वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया और लातिनी अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में इस माडल को उतारना है। महिंद्रा के एक कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि यह वाहन भारत में अप्रैल 2027 में स्कांर्पियो लाइफस्टाइलर नाम से पेश किया जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे महिंद्रा लाइफस्टाइलर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इस पिकअप को विशेष रूप से वैश्विक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और यह कंपनी की वैश्विक विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशियाई (आसियान) बाजारों में भी इसकी संभावनाओं का जिक्र किया, जहां कंपनी नए उत्पादों के साथ अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। कंपनी फिलहाल इंडोनेशिया को छोड़कर आसियान क्षेत्र के अन्य बाजारों में मौजूद नहीं है। वित्त वर्ष 2025-26 में महिंद्रा का वाहन निर्यात 18.2 प्रतिशत बढ़कर 41,030 इकाई रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के 34.700 वाहन के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

एसबीआई का कारोबार 2030 तक 200 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान, बैंक चेयरमैन ने मौजूदा वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से जोड़ा अनुमान



नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का कुल कारोबार वर्ष 2030 तक 200 लाख करोड़ रुपये के विशाल आंकड़े को छू सकता है। बैंक के चेयरमैन सीएस. शेण्डी ने यह अनुमान मौजूदा वृद्धि दर और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत गति के आधार पर व्यक्त किया है, जो बैंक के 75वें स्थापना दिवस के करीब एक बड़ी उपलब्धि होगी। चेयरमैन शेण्डी ने एक साक्षात्कार में बताया कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था 7-8 प्रतिशत की दर से बढ़ती है, तो एसबीआई के बही-खाते में सालाना 11-12 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे बैंक का कारोबार लगभग हर छह साल में दोगुना हो जाएगा। जून 2023 के अंत में एसबीआई का कुल कारोबार 110.01 लाख करोड़ रुपए था।

नईदुनिया

त्योहारों से पहले खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव: सस्ते आयातित मजबूत, महंगे देसी नरम

घरेलू तेल 20-24 रुपए प्रति किलो महंगे होने से मांग प्रभावित, आयातित तेलों की धूम

नई दिल्ली
आगामी त्योहारों के मद्देनजर बीते सप्ताह खाद्य तेल बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। देशी तेलों के मुकाबले 20-24 रुपए प्रति किलो सस्ता होने के कारण सोयाबीन तेल, कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन जैसे आयातित खाद्य तेलों के दाम मजबूत हुए। वहीं ऊंचे दाम के चलते घरेलू सरसों तेल-तिलहन और सोयाबीन तिलहन में गिरावट दर्ज की गई। बाजार सूत्रों के अनुसार देशी तेलों की तुलना में सस्ता होने से आगामी त्योहारों में मांग बढ़ने के

कारण आयातित सोयाबीन तेल, सीपीओ और पामोलीन के दाम मजबूत रहे। विदेश में मजबूती के बावजूद आयातक इन्हें लागत से नीचे बेच रहे हैं, जिससे इनकी औद्योगिक मांग बढ़ी है। दूसरी ओर ऊंचे दाम के चलते लिवाली प्रभावित रहने से सरसों तेल-तिलहन के दाम मामूली रूप से गिरे। सोयाबीन संयंत्रों द्वारा खरीद मूल्य घटाए जाने से सोयाबीन तिलहन में भी गिरावट आई। मूंगफली तेल-तिलहन के दाम ऊंचे भाव पर कमजोर मांग के बीच स्थिर बने रहे। बिनोला तेल की उपलब्धता कम होने और ब्रांडेड कंपनियों की औद्योगिक मांग बढ़ने से इसके दाम में सुधार देखा गया। सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह सरसों दाना 50 रुपये की गिरावट के साथ 8,250-8,300 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

इसी प्रकार सरसों तेल दादरी 50 रुपये की गिरावट के साथ 16,700 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल भी क्रमशः 5-5 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 2,720-2,820 रुपये और 2,720-2,870 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाना और सोयाबीन लुज का थोक भाव क्रमशः 125-125 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 6,775-6,825 रुपये और 6,625-6,725 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। दूसरी ओर, दिल्ली में सोयाबीन तेल 125 रुपये के सुधार के साथ 15,800 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 125 रुपये के सुधार के साथ 15,650 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल 200 रुपये के सुधार के साथ 12,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

बीते सप्ताह मूंगफली तिलहन का दाम 7,350-7,925 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 17,000 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाईंड तेल 2,680-2,980 रुपये प्रति टिन पर स्थिर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सीपीओ तेल का दाम भी 250 रुपये के सुधार के साथ 13,950 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली 275 रुपये के सुधार के साथ 15,850 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल 275 रुपये के सुधार के साथ 14,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। ब्रांडेड कंपनियों की औद्योगिक मांग बढ़ने और उपलब्धता कम रहने के बीच बिनोला तेल का दाम 25 रुपये के सुधार के साथ 17,125 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

यूपीआई ग्राहकों की जेब सुरक्षित एमडीआर का बोझ रोकने की तैयारी

आरबीआई के पुराने नियम का सहारा, डेबिट कार्ड माडल पर बनेगी नई नीति, छोटे दुकानदारों के लिए यूपीआई रहेगा मुफ्त

नई दिल्ली
देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार और नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपलसीआई) एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे यूपीआई पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का बोझ ग्राहकों की जेब पर न पड़े। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उस पुराने नियम को आधार बनाया जा सकता है, जो डेबिट कार्ड से भुगतान पर दुकानदारों को ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेने से रोकता है। चूंकि यूपीआई पिछले छह सालों से मुफ्त है, इसलिए इस तरह के नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन अब जब बड़े व्यापारियों पर शुल्क लगाने की चर्चाएं हो रही हैं, तो इस बात का डर है कि व्यापारी इसे ग्राहकों से वसूलना शुरू न कर दें। इसी आशंका को दूर करने के लिए एनपीसीआई अपने यूपीआई सफ़्ट्वेयर में भी डेबिट कार्ड वाले नियम की तरह एक क्लॉज जोड़ने पर विचार कर रहा है। दिसंबर 2017 में आरबीआई ने डेबिट कार्ड के लेनदेन पर बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दुकानदार यह शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। यूपीआई पर इस नियम को लागू कराने की अंतिम जिम्मेदारी आरबीआई की ही होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेमेंट्स कार्डसिल आफ इंडिया (पीसीआई) पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि यूपीआई पर एमडीआर लागू होता भी है, तो वह सिर्फ़ व्यापारियों के लिए होगा, आम ग्राहकों के लिए नहीं। इसके अलावा, छोटे दुकानदारों को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा और उनके लिए यूपीआई सेवाएं मुफ्त ही रहेंगी। गैजेट नोटिफिकेशन आने के बाद एनपीसीआई और यूपीआई स्टैंडर्डिंग कमेटी मिलकर एमडीआर का बांटा तय करेंगी। हालांकि, कागजों पर नियम बनाना आसान है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना चुनौती भरा होगा। फिनटेक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि बैंकों के लिए इसे लागू करना मुश्किल होगा।



एफएसएसएआई का शिकंजा, फूड दिग्गजों से ई-कामर्स, रेस्टोरेंट तक निशाने पर, भ्रामक विज्ञापन, गलत दावे और लेबलिंग उल्लंघन पर 150 को नोटिस

नई दिल्ली। देश के खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने नेस्ले, पेप्सीको, कोका-कोला जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर एमेज़ान और केएफसी जैसे ई-कामर्स व रेस्टोरेंट ब्रांड्स तक पर सख्त कार्रवाई की है। पिछले कुछ महीनों में कथित तौर पर भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर 150 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। एफएसएसएआई ने नेस्ले, पेप्सिको, कोकाकोला सहित कई प्रमुख फूड बिजनेस आपरेटर्स को गलत दावों, भ्रामक विज्ञापनों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर नोटिस भेजे। इस कार्रवाई के तहत कई कंपनियों के उत्पाद जब्त भी किए गए हैं। नियामक का शिकंजा सिर्फ़ निर्माताओं तक सीमित नहीं रहा। एमेज़ान और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कामर्स कंपनियों के साथ-साथ केएफसी, मैकडोनेल्ड, पिज्जा हट और डोमोनिज जैसे रेस्टोरेंट चेन को भी नोटिस जारी हुए हैं। कार्रवाई के परिणामस्वरूप एमेज़ान के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द हुआ, वहीं डोमोनिज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एफएसएसएआई का मुख्य लक्ष्य ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचाना और खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। नियामक ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद कई कंपनियों ने सुधारामक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एफएसएसएआई का यह सख्त रुख भविष्य में भी जारी रहेगा, और ऐसी कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।



टाटा स्टारबक्स अपने स्टोर की संख्या बढ़ाने की तैयारी में



मुंबई। भारत में काफी चैन स्टारबक्स एक बार फिर आक्रामक विस्तार रणनीति अपनाने जा रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि. (टीसीपीएल) के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले डेढ़-दो साल में कारोबारी माडल को नए सिरे से तैयार करने के बाद कंपनी को कारोबार में स्पष्ट सुधार के संकेत मिले हैं, जिसके चलते अब स्टोर खोलने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। टाटा स्टारबक्स ने लगातार चार तिमाहियों में समान स्टोर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है और अब बिक्री में तेजी भी दिख रही है। वर्तमान में भारत में करीब 500 स्टारबक्स कैफे संचालित करने वाली टाटा स्टारबक्स की योजना अब मौजूदा लगभग 80 शहरों में ही स्टोर की संख्या (घनत्व) बढ़ाने पर है, न कि केवल नए शहरों में पहुंचने पर। डिजिटल ने बताया कि कंपनी ने पिछले दो वर्षों में स्टोर के आकार, प्रति स्टोर पूंजीगत खर्च और पेय पदार्थों की कीमतों सहित अपने पूरे कारोबारी माडल की समीक्षा की है, ताकि इसे अधिक टिकाऊ बनाया जा सके। जून तिमाही में टाटा स्टारबक्स का राजस्व 11 प्रतिशत बढ़ा और इस दौरान चार नए स्टोर भी खोले गए, जिनमें दो रिजर्व स्टोर शामिल हैं। टीसीपीएल के अधिकारी ने जून में कहा था कि टाटा स्टारबक्स की दीर्घावधि महत्वाकांक्षा चीन के स्तर (लगभग 8,000 स्टोर) तक पहुंचने की है।

भारत का दक्षिण अमेरिका पर फोकस, व्यापार विस्तार को वाणिज्य सचिव की हरी झंडी

चिली से वृहद समझौता, अर्जेंटीना व ब्राजील संग मर्कोसुर पीटीए विस्तार एजेंडे में

नई दिल्ली
भारत अपनी व्यापार विविधीकरण रणनीति के तहत दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल 24 से 28 अगस्त तक चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा करेंगे, जहां वे प्रमुख व्यापार समझौतों की समीक्षा और विस्तार पर चर्चा करेंगे। यह दौरा इन तेजी से बढ़ते बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल है। यात्रा के दौरान अग्रवाल चिली के साथ प्रस्तावित वृहद आर्थिक साझेदारी समझौते (सीडीपीए) की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे, जो अंतिम चरण में है।



बाजार पहुंच और महत्वपूर्ण खनिज जैसे मुदे लंबित हैं। यह समझौता 2006 के त्रिजोही व्यापार समझौते का स्थान लेगा और डिजिटल सेवाओं व निवेश को भी शामिल करेगा। 2025-26 में भारत-चिली व्यापार 66.45 प्रतिशत बढ़कर 6.25 अरब डॉलर (रुपए) हो गया, जो सबसे तेज वृद्धि है। अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ बैठकों में भारत-मर्कोसुर त्रिजोही व्यापार समझौते के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में केवल लगभग 450 शुल्क लाइनें

शामिल हैं। ब्राजील के साथ विश्व व्यापार संगठन में चल रहे चीनी विवाद पर भी चर्चा की उम्मीद है। ये देश चीन पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे। 2025-26 में अर्जेंटीना के साथ भारत का व्यापार 5.96 अरब डॉलर (रुपए) और ब्राजील के साथ 15 अरब डॉलर (रुपए) रहा। यह पहल नए बाजारों की तलाश और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की भारत की व्यापक रणनीति का अहम हिस्सा है।

छोटी कंपनियों पर फंड मैनेजरों का बड़ा दांव, लंबे समय तक बने रहने की रणनीति

स्मालकैप फंडों में भारी निवेश, एयूएम में जबरेदस्त उछाल, लाकड़न अवधि के बाद भी अटूट भरोसा

नई दिल्ली
घरेलू म्यूचुअल फंड छोटी कंपनियों और उनके आईपीओ (आईपीओ) में एक भरोसेमंद व धैर्यवान निवेशक के तौर पर उभर रहे हैं। वे एंकर निवेशक के तौर पर एक बार निवेश करने के बाद लंबे समय तक उसमें बने रहते हैं, जबकि विदेशी निवेशक तेजी से मुनाफावसूली करते हैं। हालिया आंकड़ों और बाजार नियामक सेबी के एक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्मालकैप में घरेलू फंडों का भरोसा लगातार गहरा रहा है। फंड मैनेजर इन दिनों छोटी कंपनियों पर बड़ा दांव लगा रहे हैं और एंकर निवेशक के तौर पर उनमें निवेश करने के बाद 90 दिनों की लाक-इन अवधि समाप्त होने के बावजूद लंबे समय तक अपनी



हिस्सेदारी बनाए रखते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान, स्मालकैप फंडों की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां निवेश को भी शामिल करेगी। 2025-26 में भारत-चिली व्यापार 66.45 प्रतिशत बढ़कर 6.25 अरब डॉलर (रुपए) हो गया, जो सबसे तेज वृद्धि है। अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ बैठकों में भारत-मर्कोसुर त्रिजोही व्यापार समझौते के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में केवल लगभग 450 शुल्क लाइनें

फंड मैनेबोर्ड आईपीओ में असाधारण धैर्य दिखाते हैं। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2025 के बीच 242 आईपीओ के विश्लेषण में, म्यूचुअल फंडों ने 30 दिन की लाक-इन अवधि के बाद अपने आवंटन के औसतन केवल 3 फीसदी हिस्से की बिकवाली की। यह आंकड़ा 60वें दिन तक 7 फीसदी और 90वें दिन तक 15 फीसदी की रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि 100 से अधिक आईपीओ में म्यूचुअल फंडों ने 30 दिन बाद कोई बिकवाली नहीं की। 365 दिनों की होल्डिंग अवधि में भी, म्यूचुअल फंडों ने अपने आवंटन मूल्य का महज 38 फीसदी हिस्सा बेचा, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई 60 फीसदी बिकवाली के मुकाबले काफी कम है। यह दर्शाता है कि स्मालकैप और मिडकैप फंड लंबी अवधि के नजरिए से निवेश कर रहे हैं और कीमतों में वृद्धि होने पर भी आसानी से बिकवाली नहीं करते। उनका मानना है कि इनमें से कुछ कंपनियों में वास्तविक वृद्धि की क्षमता मौजूद है।